(b) The per capita net availability of wheat during 1994, 1995 and 1996 has been 159.5, 172.0 and 178.9 gms. per day.

(c) and (d) There was no import of wheat during 1994-95 and 1995-96. During 1996-97 Government decided to import upto 2 million tonnes of wheat. Against this, a quantity of 16.75 (+5%) lakh tonnes from Australia, Canada and Argentina has been contracted for import as per details given below:—

Country	Date of contract	Quantity (lakh MT)	Price US $ (per MT)
Australia	10.12.96	10.00	148.00 FOB
	31.01.97	1.25	156.00 FOB
	14.02.97	2.00	156.00 FOB
Canada	11.12.96	2.50	152.50 FOB
Argentina	4.02.97	1.00	173.00 C&F

सहारनपुर-देहरादून, देहरादून-ऋषिकेश और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल-मार्ग का सर्वेक्षण

*599. **श्री मनोहर कांत ध्यानी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार ने सहारनपुर-देहरादून, देहरादून-ऋषिकेश-कर्णप्रयाग के मध्य रेल-मार्ग का सर्वेक्षण कराने के संबंध में कोई घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इसमें अब तक कितनी धन-राशि व्यय हुई है और भविष्य में कितनी धनराशि के व्यय होने की संभावना है;

(घ) उन केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां से यह सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है तथा इस परियोजना से कितने लोग जुड़े हुए हैं; और

(ङ) क्या राज्य सरकार को इस सर्वेक्षण कार्य में योगदान करना होता है; यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई योगदान किया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां।

(ख)

खंड	लम्बाई कि० मी० में	प्रगति
सहारनपुर-देहरादून	69	फील्ड कार्य पूरा हो गया है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
देहरादन-ऋषिकेश	30	50 प्रतिशत
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग	185	10 प्रतिशत

(ग)

खंड	अब तक खर्च की गई राशि (30.4.97)	खर्च की जाने वाली संभावित राशि (लाख रुपयों में)
सहारनपुर-देहरादून	4.00 रु०	0.20 रु०
देहरादून-ऋषिकेश	0.50 रु०	0.40 रु०
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग	0.60 रु०	9.40 रु०

(घ)

खंड	स्थान	संबद्ध व्यक्तियों की संख्या
सहारनपुर-देहरादून	उप मुख्य इंजीनियर/ निर्माण, गाजियाबाद	मुख्य इंजीनियर/सर्वेक्षण के अधीन उत्तर रेल का
देहरादून-ऋषिकेश	-वही-	सर्वेक्षण संगठन तथा व्यावसायिक
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग	उप मुख्य इंजीनियर/सर्वेक्षण, नई दिल्ली तथा अपने फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से रूड़की विश्वविद्यालय	यूनिटों जैसे रूड़की विश्वविद्यालय आदि द्वारा भी सहायता की गई है।

(ङ) जी नहीं।

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव

*600. **श्री ओम प्रकाश कोहली:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में आरंभ की गई 'मध्याह्न भोजन योजना' का क्या प्रभाव पड़ा है तथा इससे यह कहां तक सुनिश्चित हुआ है कि इन स्कूलों में नियमित उपस्थिति बनी रहे और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में कमी आए;

(ख) क्या सरकार ने इस दृष्टि से इस योजना के संबंध में कोई समीक्षा कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना की समीक्षा कराने का इरादा रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को बच्चों के नामांकन, उनकी उपस्थिति को बढ़ावा तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के आहार पर प्रभाव डालकर प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था। वर्ष 1997-98 में, यह योजना 507 जिलों के 5440 ब्लाकों के लगभग 6 लाख स्कूलों में 8.68 करोड़ बच्चों को शामिल करने तक ही सीमित है।

चूंकि यह योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है अतः बच्चों की उपस्थिति तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, अभी तक कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं कराया गया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों ही द्वारा की जाती है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उन्हें देखने से पता चला है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन तथा उनकी उपस्थिति पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Subsidies to Farmers

4424. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the different types of indirect and direct subsidies being given to farmers and their annual impact;

(b) which of these are oriented towards small and marginal farmers and poorer sections of the farming population;

(c) whether any study has been undertaken to verify whether such subsidies reach the targeted populatin; if so, the results thereof; and

(d) if not, in what manner it is ensured that these subsidies actually reach the targeted population?